

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 285 राँची, मंगलवार,

19 वैशाख, 1938 (श॰)

9 मई, 2017 (ई॰)

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना 4 मई, 2017

संख्या-एल॰जी॰-32/2015-54/लेज॰-- झारखंड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर राज्यपाल दिनांक 20 अप्रैल, 2017 को अनुमति दे चुकीं है, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है।

झारखण्ड पर्यटन स्थल (संरक्षण एवं रख-रखाव) (संशोधन) अधिनियम] 2016 (झारखंड अधिनियम संख्या-11, 2017)

झारखण्ड पर्यटन स्थल (संरक्षण एवं रख-रखाव) अधिनियम, 2015 में संशोधन हेतु विधेयक । झारखण्ड विधान सभा द्वारा भारत के गणतंत्र के सड़सठवें वर्ष में निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाता है ।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ -

- (क) यह अधिनियम झारखण्ड पर्यटन स्थल (संरक्षण एवं रख-रखाव) (संशोधन) अधिनियम, 2016 कहलाएगा ।
- (ख) यह झारखण्ड राज्य के सम्पूर्ण क्षेत्र पर लागू होगा ।
- (ग) यह राजकीय गजट में अधिसूचित होने की तिथि से लागू होगा ।
- 2. धारा 2 की उपधारा (छ) में संशोधन -

झारखण्ड पर्यटन स्थल (संरक्षण एवं रख-रखाव) अधिनियम, 2015 के धारा 2 के विद्यमान उपधारा (छ) में वर्णित शब्द "पर्यटक वार्डन को "सहायक (पर्यटक) पुलिस' से प्रतिस्थापित किया जाता है।

3. धारा 4 की उपधारा (घ) में संशोधन -

झारखण्ड पर्यटन स्थल (संरक्षण एवं रख-रखाव) अधिनियम, 2015 के धारा 4 के विद्यमान उपधारा (घ) में वर्णित शब्द "पर्यटक वार्डन' को "सहायक (पर्यटक) पुलिस' से प्रतिस्थापित किया जाता है।

4. धारा 17 की उपधारा (छ) में संशोधन -

झारखण्ड पर्यटन स्थल (संरक्षण एवं रख-रखाव) अधिनियम, 2015 के धारा 17 के विद्यमान उपधारा (छ) में वर्णित शब्द "पर्यटक वार्डन" को "सहायक (पर्यटक) पुलिस" से प्रतिस्थापित किया जाता है।

5. धारा 2 की उपधारा (छ) में संशोधन -

झारखण्ड पर्यटन स्थल (संरक्षण एवं रख-रखाव) अधिनियम, 2015 धारा 2 के विद्यमान उपधारा (छ) को निम्नलिखित रूप से संशोधित किया जाता है:-

"सहायक (पर्यटक) पुलिस से अभिप्राय है वैसे व्यक्तियों की नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति जो कि सक्षम प्राधिकार द्वारा या तो सेवा निवृत पुलिस अधिकारी या तो भूतपूर्व सैनिक से सैनिक कल्याण बोर्ड द्वारा चयनित या स्थानीय शिक्षित बेरोजगार युवकों के बीच से चयनित, अथवा ऐसे सरकारी कर्मी जिनको इस कार्य हेतु प्राधिकृत किया जाए'।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

दिनेश कुमार सिंह, प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी विधि विभाग, झारखंड, राँची ।

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना 4 मई, 2017

संख्या-एल॰जी॰-32/2015-55/लेज॰-- झारखंड विधान मंडल द्वारा यथा पारित और राज्यपाल द्वारा दिनांक 20 अप्रैल, 2017 को अनुमत झारखण्ड पर्यटन स्थल (संरक्षण एवं रख-रखाव) (संशोधन) अधिनियम, 2016 का निम्नांकित अंग्रेजी अनुवाद झारखंड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

The Jharkhand Tourist Places (Protection and Maintenance) (Amendment) Act, 2016

(JHARKHAND ACT, 11, 2017)

An Act to amend the Jharkhand Tourist Places (Protection and Maintenance) Act, 2015.

Be it enacted by the Legislative Assembly of the State of Jharkhand in the Sixty Seven Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title, extent and commencement –

- (i) This Act may be called The Jharkhand Tourist Places (Protection and Maintenance) (AMENDMENT) Act, 2016.
- (ii) It extends to the whole of the State of Jharkhand.
- (iii) It shall come into force on the date of its publication in the government gazette.

2. Amendment in sub section (g) of section 2:-

In sub section (g) of section 2 of the Jharkhand Tourist Places (Protection and Maintenance) Act, 2015 (herein after referred to as the Principal Act), for the word "TOURIST WARDEN" the word "ASSISTANT (TOURIST) POLICE" shall be substituted.

3. Amendment in sub section (iv) of section 4:-

In sub section (iv) of section 4 of the Principal Act, for the word "TOURIST WARDEN" the word "ASSISTANT (TOURIST) POLICE" shall be substituted.

4. Amendment in sub section (vii) of section 17:-

In sub section (vii) of section 17 of the Principal Act, for the word "TOURIST WARDEN" the word "ASSISTANT (TOURIST) POLICE" shall be substituted.

5. Amendment in sub section (g) of section 2:-

The existing sub section (g) of section 2 of the Principal Act, shall be substituted in the following manner:-

"ASSISTANT (TOURIST) POLICE means those persons appointed / deputed by the competent authority either from Retired Police officer OR Ex-Servicemen selected through army welfare board OR from educated unemployed youth from the local community OR any other government servant deputed / authorised for the same purpose".

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

दिनेश कुमार सिंह, प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी विधि विभाग, झारखंड, राँची ।
